भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

10.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2847 का उत्तर

पश्चिम बंगाल में चालू रेलवे परियोजनाएं

2847. श्री खगेन मुर्मुः
डॉ. सुकान्त मजूमदारः
श्री विनोद कुमार सोनकरः
श्री सप्तगिरी उलाकाः
श्री एस.आर. पार्थिबनः
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश की अनेक रेलवे परियोजनाएं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में बहुत ही धीमी गति से प्रगति कर रही हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना-वार वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) रेल परियोजनाओं का समय, वित्तपोषण का स्रोत और लागत में वृद्धि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) नई रेलवे परियोजनाओं के लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा इन रेलवे परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): इस समय, पश्चिम बंगाल में 42734 करोड़ रु. लागत वाली 4427 किमी. लम्बी 54 परियोजनाओं, उत्तर प्रदेश में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली 88213 करोड़ रु. की लागत वाली 6604 कि.मी. लम्बी 79 परियोजनाओं, ओडिशा में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 47912 करोड़ रु.

की लागत वाली 4537 किमी. लम्बी 35 परियोजनाओं, तमिलनाडु में पूर्णतः/अंशतः आने वाली 21829 करोड़ रु. लागत वाली 2519 किमी. लम्बी 22 परियोजनाओं, कर्नाटक में पूर्णतः/अंशतः आने वाली 41746 करोड़ लागत वाली 4417 किमी. लम्बी 35 परियोजनाओं और गुजरात में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 24786 करोड़ रु. की लागत वाली 3600 कि.मी. लम्बी 40 परियोजनाओं सहित 491 रेल परियोजनाएं नियोजन/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

इन 491 रेल परियोजनाओं की कुल लम्बाई 48861 कि.मी. और लागत 6.48 लाख करोड़ रु. है। मार्च 2019 तक इन परियोजनाओं पर कुल 1.43 लाख करोड़ रु. खर्च किए गए हैं और 9113 कि.मी. लम्बाई पर यातायात चालू किया गया है।

बहरहाल, प्रत्येक परियोजना पर खर्च की गई धनराशि, आबंटित धनराशि और खर्च सहित सभी चालू तथा नए कार्यों का ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात् www.indianrailways.gov.in >Ministry of Railways >Railway Board >About Indian Railways >Railway Board Directorates >Finance(Budget) >2019-20_List_of_Works में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, उल्लंघनकारी उपयोगिताओं का अंतरण (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों पर), विभिन्न प्राधिकारियों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, भूकंप, बाढ, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल, जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, माननीय न्यायालय के आदेश, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तें आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना की निष्पादन की लागत को प्रभावित करते हैं, जिसकी अंत में पूरा होने की स्थिति पर गणना की जाती है।

समग्र राष्ट्र हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना बिना लागत में वृद्धि के पूरी हो जाएं, रेलवे में विभिन्न स्तरों (फील्ड स्तर, मंडल स्तर, क्षेत्रीय स्तर और बोर्ड स्तर) पर काफी निगरानी की जाती है और परियोजना की प्रगति में बाधा डालने वाले लंबित मामलों को सुलझाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं।

sk

यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाएं समय से पहले भी पूरी हो जाती हैं, रेलवे ने निविदा में बोनस क्लॉज के रूप में ठेकेदार को प्रोत्साहन की अवधारणा को अपनाया है जो परियोजना के निष्पादन की गति में और वृद्धि करेगा।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं, क्षमता संवर्धन संबंधी परियोजनाओं, अंतिम स्थान संपर्कता आदि के लिए 1.5 लाख करोड़ रु. के ऋण द्वारा संस्थागत वित्तपोषण की व्यवस्था की गई है जिससे अनिवार्य परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध निधि व्यवस्था से रेलवे की क्षमता में वृद्धि हुई है।

*****

sk